SPECIAL MENTIONS

Demand for constructing buildings for CGHS dispensaries running in rented accomodation

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): सभापति जी, केन्द्र सरकार द्वारा आदरणीय सांसदों-पूर्व सांसदों, उनके परिजनों एवं केन्द्र सरकार के कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है। लाभार्थी एवं उनके परिजन इन औषधालयों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए प्राय: आते-जाते रहते हैं, इसलिए यह भी अपेक्षा रहती है कि औषधालयों में आधारभूत सुविधाएं इस प्रकार व्यवस्थित की जाएं कि लाभार्भियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। स्वास्थ्य मंत्रालय भी समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी करता रहता है, ताकि लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधाएं यथाशीघ्र मिलें और उन्हें कोई असुविधा न हो। अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं के अभाव में लाभार्थी को कष्टकारक स्थिति का सामना करना पड़ता है।

सभापति जी, पूरे देश में स्थापित इन सीजीएचएस औषधालयों में कई औषधालयों के पास अपने भवन नहीं हैं। ये औषधालय किराए के भवन में चल रहे हैं। परिणामस्वरूप जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए तथा बदलती हुई जरूरत के हिसाब से जो विस्तार होना चाहिए, वह संभव नहीं हो पाता है। दिल?ली-एनसीआर में कई औषधालय हैं, जिनके अपने भवन नहीं हैं। ऐसे में यदि फैमिली प्लानिंग या शिशु टीकाकरण की सुविधा का विस्तार करना हो, तो स्थान का अभाव आड़े आ जाता है। नोएडा में सेक्टर-82 में केन्द्रीय विहार स्थित डिस्पेंसरी की हालत भी ऐसी ही है। किराए के भवन में चलने की वजह से आधारभूत सुविधाओं का अत्यंत अभाव है।

मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि जितने भी औषधालय किराए के भवन में चल रहे हैं, उनके लिए चरणबद्ध आधार पर प्राथमिकता से भवन का निर्माण कराया जाए।

MR. CHAIRMAN: Please; in spite of my caution, you are doing it. This is not theway.

वहाँ से यहाँ ऐसे ही नहीं जाना और जाना है, तो उसके लिए तरीका है।

Demand for giving PIB accreditation to digital journalists

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Hon. Chairman, Sir, with your permission, I am raising, under Special Mentions, PIB accreditation of digital journalist.

Sir, in Journalism there has been a new development over the past few years which has raised the voice of the marginalized/underprivileged, i.e. digital journalism, ensuring that no story can go untouched and unverified. The trust in digital

[Prof. Manoj Kumar Jha]

journalism has risen so much that even the print and television, all mediums have opened their online content. It is high time that the Government consider PIB accreditation for the digital journalists also. The accreditation is only limited to print and television journalists at present. Digital media is the most democratic space where the information is sent at the speed of light. Digital media has empowered people. The digital space permits handling of a subject with multiple viewpoints. It is richer in terms of content and constitutional values. But, people working in digital space are not able to visit Parliament during sessions. The accreditation will enable them to contribute more towards journalism, the fourth pillar of democracy.

The Parliamentary sessions and speeches of the hon. Member of Parliaments reach public via digital media mostly. The television and print has limited role in this matter. Earlier, only television telecast was the medium through which the public could access the speeches in the Houses. Those who missed could never watch it. But, digital journalists have made sure that not only clips of MPs, but, the debate and discussions on those clips too reach to the public. In 21st Century of digital India, the journalists working in Digital Media must be given the facility of accreditation by PIB. Thank you.

Demand to give the status of Central University to the Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): महोदय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में सबसे उन्नत नगर के रूप में जाना जाता है। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित है। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही नहीं हैं, बल्कि इसमें पढ़ने वाले छात्र पश्चिम बिहार तथा नेपाल के भी हैं। यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। अंतर्राज्यीय विश्वविद्यालय माना जाने वाला यह विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय विश्वविद्यालय की तरह शिक्षा नहीं दे पा रहा है। गुणवत्ता भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की तरह नहीं है। नेपाल तथा पश्चिम बिहार के छात्रों को शिक्षा देने वाले इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना आवश्यक है।

अत: सरकार तथ्यों का संज्ञान लेते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने पर सहमति प्रकट करे।

MR. CHAIRMAN: Shri CM. Ramesh, not present. Dr. Kirodi Lai Meena.